# वित्त लेखे. संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

## भारत सरकार लेखा मानक: 3

#### **INDIAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD: 3**

#### सं.3 - संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों का विवरण No. 3-STATEMENT OF LOANS AND ADVANCES MADE BY THE UNION GOVERNMENT

#### भागः 1 ऋणों और अग्रिम राशियों का सारांश : ऋणी समृहवार

Section: 1 Summary of Loans and Advances: Loanee group wise

जोड़ TOTAL	<b>55839373.12</b> *-195676.00	23220442.11	2494810.40	_	76369328.83	-20725631.71	4674117.78
सरकारी कर्मचारी Government Servants	22464.30	16698.38	9351.02	_	29811.66	-7347.36	-
Non-Government Institutions, Local Funds, Cultivators etc.	*-195676.00						
सरकारी निगम, गैर—सरकारी संस्थाएँ, स्थानीय निधियां, किसान आदि Government Corporations,	23020177.25	#3532345.63	684810.92	-	25672035.96	-2847534.71	4221318.45
Foreign Governments	1445620.18	44342.50	43781.73	_	1446180.95	-560.77	_
Union Territory Governments विदेशी सरकारें	425632.91	1113445.00	7748.98	_	1531328.93	-1105696.02	271633.64
राज्य सरकारें State Governments संघ राज्य क्षेत्र सरकारें	30925478.48	18513610.60	1749117.75	_	47689971.33	-16764492.85	181165.69
<u>`</u>						(Ir	(लाख रुपयों में) a lakhs of rupees)
1	April 1, 2021 2	during the year 3	during the year 4	irrecoverable loans and advances 5	March 31, 2022 (2+3)-(4+5) 6	decrease during the year (2-6)	payment in arrears 8
Loanee Group	Balance on	Disbursements	Repayments	बट्टे खाते डालना Write-off of	(2+3)-(4+5) Balance on	कमी (2-6) Net increase/	ब्याज अदायगी Interest
ऋणी समूह	01 अप्रैल, 2021 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान चुकौती	अप्रतिसंहरणीय कर्ज और अग्रिम को	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि /	बकायों में

#### टिप्पणियां :

Out of total amount of ₹19627055.60 lakh paid as loans to State/Union Territory Governments, Nil loans has been granted to cover gaps in resources of the State/Union Out of total alliculus of \$19027033.00 lakil paid as loans to State/Ollion Territory Governments, Ni loans ha Territory Governments. पिछले वर्ष में गलत वर्गीकरण को ठीक करने के लिए पूर्व अवधि समायोजन (पीपीए) को दर्शाता है। Represent Prior Period Adjustment (PPA) to rectify misclassification in previous year. पीएसबी को वितरित किए गए ₹14724 लाख की राशि के ऋण को गारंटी रिडेम्पशन फंड से लिया गया था।

Loan disbursed to PSBs amounting to ₹ 14724 Lakh was met from Guarantee Redemption Fund.

किया गया कर्ज शुन्य राशि था।

- 2. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ₹ 233459.91 लाख की पुनर्अदायगी 31 मार्च, 2022 तक बट्टे खाते डाल दी गई है।
  In pursuance of the recommendations of the 13th Finance Commission, repayments by the States/Union Territories amounting to ₹ 233459.91 lakh has been written off up to March 31, 2022.
- 3. वर्ष के प्रारंभ में, राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम के रूप में स्वीकृत कोई राशि शेष नहीं थी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्रॉफ्ट के समाशोधन / परिहार के लिए अर्थोपाय अग्रिम के रूप में शून्य राशि का भुगतान किया गया था जिससे शून्य राशि शेष रही।

  At the beginning of the year, there was no balance of sanctioned amount to State Governments as Ways and Means Advances. During the year, Nil amount was paid as Ways and Means

Advances to State Government for clearance/avoidance of overdrafts from the Reserve Bank of India leaving a balance of Nil amount.

4. "शाश्वत कर्ज" के रूप में मंजूर किए गए कर्ज के मामले निम्नलिखित हैं:— Following are the cases of loan having been sanctioned as "loan in perpetuity"

(लाख रुपयों में) (In lakh of rupees) मजूरी आदेश सं ऋणी संस्था स्वीकृति वर्ष राशि क्रम संख्या ब्याज दर S. No. Loanee Entity Year of Sanction Sanction Order No. Amount Rate of Interest राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार 1. State/Union Territory Government अन्य ऋणी संस्थाएं – 2. Other loanee entities -(i) भारत संचार निगम लिमिटेड 25-1/2001-एसएटी / पीपी(भाग) दिनाक 13.01.2003 Bharat Sanchar Nigam Limited 2003-04 25-1/2001-SAT/pp(pt) 72000.00 Dated 13.01.2003 (ii) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. 8(2)/2009/एचएसएल / डी(एसवाई) का पीसी—II दिनांक 23.03.2011 PC-II to 8(2)/2009/HSL/D(SY) Hindustan Shipyard Ltd. 2010-11 37222.00 # Dated 23.03.2011 जोड TOTAL 109222.00

<sup>#</sup> ब्याज देयता के बिना शाश्वत कर्ज।

<sup>#</sup> Loan in prepetuity without any interest liability.

<sup>-</sup> कॉलम ७ में कर्ज की वृद्धि को '–' चिहन के साथ दर्शाया गया है।

<sup>-</sup> In column No. 7 increase in Loans has been shown with '-' Sign.

# वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT भारत सरकार लेखा मानक: 3

#### **INDIAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD: 3**

## सं.3 – संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों का विवरण No.3-STATEMENT OF LOANS AND ADVANCES MADE BY THE UNION GOVERNMENT

मागः 2 ऋणों और अग्रिम राशियों का सारांश : सेक्टरवार

Section: 2 Summary of Loans and Advances: Sector-wise

सेक्टर	01 अप्रैल, 2021 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अप्रतिसंहरणीय कर्जों और अग्रिम राशियों	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि /	बकायों में ब्याज
Sector	Balance on April 1, 2021	Disbursements during the year	Repayments during the year	को बट्टे खाते डालना Write-off of irrecoverable loans and advances	(2+3)-(4+5) Balance on March 31, 2022 (2+3)-(4+5)	कमी (2-6) Net increase/ decrease during the year (2-6)	अदायगी Interest payment in arrears
1	2	3	4	5	6	7	8
						(In	(लाख रुपयों में) lakhs of rupees)
सामान्य सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6075) General Services— (Major Head 6075)	_	_	_	_	_	_	_
सामाजिक सेवाएं (6202 से 6250 तक मुख्य शीर्ष) Social Services	9405551.49 * 10450.00	1894231.00	56309.71	_	11253922.78	—1837921.29	128565.35
(Major Heads from 6202 to 6250)	10 120.00						
आर्थिक सेवाएं (6401 से 7475 तक मुख्य शीर्ष और मुख्य शीर्ष 7615) Economic Services (Major Heads from 6401 to 7475 and Major Head 7615)	13614625.76 *-206126.00	1638114.63	628501.21	_	14418113.18	—1009613.42	4092753.10
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार (मुख्य शीर्ष 7601 & 7602) State and U.T. Governments (Major Head 7601 & 7602)	31351111.39	19627055.60	1756866.73	_	49221300.26	—17870188.87	452799.33

Foreign Governments (Major Head 7605) सरकारी कर्मचारी (मुख्य शीर्ष 7610) Government Servants	1445620.18 22464.30	44342.50 16698.38	43781.73 9351.02	_	1446180.95 29811.66	—560.77 —7347.36	_
(Major Head 7610) <b>जोड़ TOTAL</b>	55839373.12   * -195676.00	23220442.11	2494810.40		76369328.83	—20725631.71	4674117.78

नोटः विवरण के लिए संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों के विस्तृत विवरण के भाग 1 (विवरण सं. 15) को देखें।

Note: For details, refer Section 1 of Detailed Statement of loans and advances made by the Union Government (Statement no. 15).

<sup>-</sup> कॉलम ७ में कर्ज की वृद्धि को '–' चिह्न के साथ दर्शाया गया है। - In Column No. ७ increase in Loans has been shown with '–' Sign. \* पिछले वर्ष में गलत वर्गीकरण को ठीक करने के लिए पूर्व अवधि समायोजन (पीपीए) को दर्शाता है।

<sup>\*</sup> Represent Prior Period Adjustment (PPA) to rectify misclassification in previous year.

## वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT भारत सरकार लेखा मानक: 3

#### **INDIAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD: 3**

# सं.3— संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों का विवरण

#### No.3-STATEMENT OF LOANS AND ADVANCES MADE BY THE UNION GOVERNMENT भागः 3 राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से और अन्य ऋणी संस्था से बकाया में पुनर्अदायगी का सारांश

Section: 3 Summary of repayments in arrear from State or Union Territory Governments and other Loanee entities

ऋणी संस्था Loanee Entity		। मार्च, 2022 को बका राशि arrears as on Marcl		प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है Earliest period to which arrears relate	31 मार्च, 2022 को संस्था के विरुद्ध बकाया कुल कर्ज Total loans outstanding against the entity on March 31, 2022
1	2	3	4	5	6
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
	प्रधान Principal	ब्याज Interest	कुल Total		
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारें State/Union Territory Governments	359060.03	452799.33	811859.36	1984-85	49221300.26
अन्य ऋणी संस्थाएं Other Loanee entities	1780936.03	4221318.45	6002254.48	1957-58	1814145.12
जोड़ TOTAL	2139996.06	4674117.78	6814113.84		51035445.38

नोटः विवरणों के लिए, संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण (विवरण सं.15) के भाग 2 एवं 3 को देखें।

Note: For details, refer Section 2 & 3 of Detailed Statement of loans and advances made by the Union Government (Statement no. 15).